

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. विशेष अपील रिट याचिका संख्या 342/2024

गुलजारी लाल पुत्र स्वर्गीय श्री बनवारी लाल, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी 9-ए, तिरुपति विहार विस्तार, मंग्यावास रोड, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।

----अपीलकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के माध्यम से, सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, 22- गोदाम सर्किल, जयपुर, राजस्थान।
2. राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अपने प्रशासक के माध्यम से, प्रधान कार्यालय जी-20, कृष्णा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान।
3. प्रबंध निदेशक, राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अपने प्रशासक के माध्यम से, प्रधान कार्यालय जी-20, कृष्णा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान।
4. मुख्य प्रबंधक, राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चांदपोल शाखा, जयपुर, राजस्थान।
5. मुख्य प्रबंधक, राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रशासक, प्रधान कार्यालय जी-20, कृष्णा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान।

6. राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, स्थापना शाखा, प्रधान कार्यालय जी-20, कृष्णा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता के लिए	:	श्री हिमांशु जैन
------------------	---	------------------

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

19/07/2024

1. सुना गया।
2. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए परमादेश जारी करने की मांग वाली रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया और यह दलील दी कि अपीलकर्ता के साथ भेदभावपूर्ण ढंग से व्यवहार किया गया और वह अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स, एम्प्लॉईज सर्विस रूल्स, **2006** (इसके बाद "2006 के नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम **14** के तहत विवेकाधिकार के प्रयोग के मामले में मनमानी शक्ति का प्रयोग का शिकार है। यह नियम नियोक्ता को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पुनर्नियोजित करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा यह रुख अपनाया गया था कि सेवा विस्तार नहीं दिया गया था और केवल कुछ व्यक्तियों को पुनर्नियोजन दिया गया था। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता के पुनर्नियोजन के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा दिए गए कारण मनमाने, अनुचित और निर्णय लेने की प्रक्रिया से असंबद्ध हैं और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश को इस महत्वपूर्ण पहलू की जांच करनी चाहिए थी और अपीलकर्ता के पक्ष में राहत प्रदान करनी चाहिए थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस गलत तथ्यात्मक आधार

पर आगे बढ़े कि किसी को भी सेवा विस्तार नहीं दिया गया था, जबकि प्रतिवादियों के अनुसार, सेवा विस्तार दिया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एक बार जब अन्य व्यक्तियों को पुनर्नियोजन प्रदान किया गया था, तो अपीलकर्ता को भी अनुकूल रूप से विचार किया जाना चाहिए था।

4. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया।
5. सबसे पहले, मामले के अभिलेखों और प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए रुख से, साथ ही इस संबंध में शासी नियमों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सेवा विस्तार के लिए कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि केवल पुनर्नियोजन के लिए प्रावधान है, जैसा कि 2016 के नियमों के नियम 14 के तहत प्रदान किया गया है। सेवा न्यायशास्त्र में पुनर्नियोजन और सेवा विस्तार के बीच एक स्पष्ट अंतर है। पुनर्नियोजन का प्रावधान सेवा का विस्तार नहीं है। प्रतिवादियों द्वारा अपनाया गया रुख यह था कि सेवा विस्तार के लिए कोई प्रावधान नहीं था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता भी इस

न्यायालय के संज्ञान में सेवा विस्तार के संबंध में कोई प्रावधान नहीं ला सके। एकमात्र प्रावधान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के पुनर्नियोजन के संबंध में है। नियम 14 में निहित प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार है: -

"सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होगी, लेकिन चतुर्थ श्रेणी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी, बशर्ते कि 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारी की सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा 3 महीने के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है। जहां बैंक के हित में वांछनीय प्रतीत होता है, बोर्ड को इस नियम के तहत सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए पुनर्नियोजित करने का विवेकाधिकार होगा, लेकिन 60 वर्ष की आयु से अधिक नहीं और ऐसी शर्तों पर जैसा कि बोर्ड प्रत्येक मामले में निर्धारित कर सकता है।"

नियम प्राधिकारी को पूर्ण विवेकाधिकार देता है कि वह पुनर्नियोजन करे या नहीं। किसी व्यक्ति का पुनर्नियोजन नियोक्ता के पूर्ण विवेकाधिकार में है, जिसमें सेवा की तात्कालिक आवश्यकताएं, अनुभवी हाथों की उपलब्धता, संस्था की आवश्यकता, कार्यभार और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। भले ही

पुनर्नियोजन की आवश्यकता हो, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का पुनर्नियोजन नियोक्ता की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर करेगा, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा को ध्यान में रखा जाएगा। एक सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकार के रूप में, यह दावा नहीं कर सकता कि केवल इसलिए कि पुनर्नियोजन का प्रावधान है, एक बार जब वह आवेदन करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से पुनर्नियोजित किया जाना चाहिए।

6. हमने 31.03.2018 के प्रस्ताव की सामग्री का अवलोकन किया है, जिसमें बैंक के निदेशक मंडल ने अपीलकर्ता के सेवा रिकॉर्ड पर विस्तार से विचार किया और फिर उसे पुनर्नियोजन न देने का संकल्प लिया। जो कारण बताए गए हैं और जिन सामग्रियों को ध्यान में रखा गया है, वे केवल सेवा रिकॉर्ड से संबंधित हैं न कि किसी बाहरी सामग्री से। अपीलकर्ता के कार्य की प्रकृति और आचरण को भी ध्यान में रखा गया। इसमें यह ध्यान में रखा गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ 2012 में जारी आरोप पत्र के माध्यम से कार्यवाही की गई थी। विभागीय जांच वसूली में

समाप्त हुई, लेकिन बाद में, उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए, वसूल की गई राशि वापस कर दी गई। प्रस्ताव में अपीलकर्ता को कदाचार के संबंध में जारी एक और आरोप पत्र का भी उल्लेख है। हालांकि, बाद में उसे पदोन्नति दी गई थी। उसे 01.02.2007 को एक और नोटिस दिया गया था और 11.10.2014 की एक घटना का भी प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है। बोर्ड ने इस प्रकार, अपीलकर्ता के पूरे सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखा है और फिर अंततः, उसे पुनर्नियोजन न देने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि विभिन्न विभागीय जांचों में कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई और अंततः वे सभी आरोप जो हटा दिए गए थे, उसके काम नहीं आते। दंड लगाने के मामले में और ऐसे मामले में विवेकाधिकार के प्रयोग में जहां एक कर्मचारी को पुनर्नियोजित किया जाता है, एक अंतर किया जाना चाहिए। जबकि कर्मचारी को नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने का अधिकार है, पुनर्नियोजन की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं

है। 31.03.2018 के अपने प्रस्ताव में प्रतिवादियों द्वारा किया गया विस्तृत विचार यह दर्शाता है कि सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखा गया था। इसलिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया किसी भी प्रक्रियात्मक अनियमितता, मनमानी या अनुचितता से इस हद तक ग्रस्त नहीं है कि इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो सत्य पाए जाने की बात तो दूर कि वह अपनी राय को प्रतिस्थापित करे। एक बार जब निर्णय पर पहुंचने के लिए विचार की गई सामग्री प्रासंगिक पाई जाती है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में कारणों की पर्याप्तता की जांच नहीं की जा सकती है।

8. सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन का स्पष्ट रूप से कोई मामला नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं लगाई गई है, तो सत्य पाए जाने की बात तो दूर किसी भी कार्यवाही में।

9. इसलिए, हम अपीलकर्ता को कोई राहत देने में असमर्थ हैं।
अपील, इसलिए, खारिज की जाती है, हालांकि उन कारणों
के अतिरिक्त जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए हैं।

(आशुतोष कुमार),जे (मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव), मुख्य न्यायाधीश
एन.गांधी-तनीषा/10

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों
के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य
उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी
संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए
प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

MITALI KARWA, ADVOCATE
Office At-
O.N. 417, 4th Floor, Sunny Paradise, Tonk Road,
Jaipur- 302018
M:- (+91)9001197999
R/5754/2022